





स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण



एक कदम स्वच्छता की ओर













केंद्रीय मंत्री की कलम से

हमारे लिए नव वर्ष का आगमन नई ऊर्जी से भरने और कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। अब तक की प्रगति राज्यों, समुदायों और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। चूंकि हम मार्च 2025 के लक्ष्य के करीब पहुंच रहे हैं, हमारे प्रयासों को तेज करना महत्वपूर्ण है। SBM-G का विस्तार हमें अतिरिक्त समय प्रदान करता है, फिर भी यह जरूरी है कि हम नियमित समीक्षाओं को प्राथमिकता दें, राज्य-स्तरीय समन्वय को मजबूत करें और गति को बनाए रखने के लिए सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ाएं। हमें यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक गांव स्वच्छता, साफ-सफाई और स्थिरता का एक मॉडल बन जाए, जो वास्तव में स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप दे, इस समय का बुद्धिमानी से उपयोग करने की आवश्यकता है।



श्री सी. आर. पाटिल केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

नए साल की शुरुआत SBMG की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों पर फिर से ध्यान केंद्रित करने का एक सही अवसर है। चूंकि हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रयासरत हैं, संचालन और रखरखाव, धन का तेजी से उपयोग तथा समय पर कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी, हमारे मिशन के केंद्र में बनी हुई है। स्वच्छता को सांस्कृतिक पहुंचान से जोड़कर और स्वच्छता में गर्व की भावना को बढ़ावा

देकर, हम सामुदायिक स्वामित्व को गहरा कर सकते हैं और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं।

श्री वी. सोमण्णा

केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वॉल्यूम १ | इश्यू २५





सचिव की कलम से

सभी राज्यों के परस्पर सहयोग और सामंजस्यता कार्यक्रम के दीर्घकालिक प्रभाव को सनिश्चित करने की आधारशिला हैं। एक साथ काम करके, सर्वोत्तम व्यवहारों को साझा करके और एकीकृत दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, हम अपने प्रयासों की पहंच तथा प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। प्रौद्योगिकी को अपनाना और व्यवहारवादी परिवर्तन अभियानों पर अधिक ध्यान देना, विशेष रूप से उन पर जो अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन का समाधान



करते हैं, स्थायी परिणाम लाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। जागरूकता का प्रसार करने, सफलताओं का प्रकटन करने और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए सहयोगी के रूप में मीडिया के साथ मिलकर कार्य करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। हमें भागीदारी का निर्माण जारी रखना चाहिए और एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रामीण भारत हासिल करने के अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए। आप सभी को आने वाले वर्ष की शुभकामनाएं।

श्री अशोक कुमार कालुराम मीना सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय



मिशन निदेशक की कलम से

हम नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं, अब SBM-G पर नए सिरे और अभिनव कार्यनीतियों के साथ से ध्यान देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी निरंतर सफलता और विकास सुनिश्चित करने के लिए - स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने, महिलाओं को मिशन के लिए केंद्रीय बनाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी में तेजी लाने, संचार प्रोटोकॉल को फिर से स्थापित करने तथा प्रशिक्षण और तकनीकी हस्तक्षेप को बढाने वाला एक स्मार्ट दृष्टिकोण हमारे प्रयासों

के मल में बना रहना चाहिए। यह समग्र और आगे की सोच वाला दृष्टिकोण न केवल हमारी उपलब्धियों को सुदृढ़ करेगा बल्कि यह गहन सामुदायिक जुडाव और स्थायी परिणामों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। आइए, हम सब मिलकर इस विजन को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों और 2025 को भारत में ग्रामीण स्वच्छता के लिए एक निर्णायक वर्ष बनाएं।



संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय





D

U

S





कार्यक्रम की उपलब्धियां

21 जनवरी, 2025 की स्थिति के अनुसार

भारत के **5.62 लाख** से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

उदीयमान: 1,32,538उज्ज्वल: 9,989उत्कृष्ट: 4,19,909सत्यापित: 2,54,690

4,87,277 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है **5,17,340** गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है

1,415 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत 998 कार्यशील बायोगैस संयंत्र

4,622 ब्लॉकों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है









कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

- किसानों और VIPs सहित सभी हितधारकों को शामिल करते हुए स्वच्छ भारत पखवाड़ा गतिविधियों को उल्लिखित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भागीदारी के साथ स्वच्छता गतिविधियों में VIPs/VVIPs (केंद्रीय मंत्री, सांसद और गणमान्य व्यक्ति) की भागीदारी।
- VIPs और VVIPs के नेतृत्व में मेगा प्लॉगिंग इवेंट्स, वॉकथॉन, स्वच्छता रैलियों और स्वच्छता रथों का आयोजन।
- जैविक अपशिष्ट के उपयोग, कचरे से धन सृजन और पॉलिथीन मुक्त दर्जा हासिल करने सहित अपशिष्ट प्रबंधन पद्धतियों की समीक्षा।
- सार्वजनिक स्थानों, सामुदायिक बाजारों और पर्यटन स्थलों की सफाई, निदयों के किनारे, तालाबों और समुद्र तटों को साफ करने के लिए टीमों को जुटाना।

निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने वाले अभियान:

- सीवरेज और पानी की लाइनों की सफाई।
- कृषि/बागवानी के लिए अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और जल संचयन के बारे में जागरूकता बढ़ाना।
- किसानों को आमंत्रित करके और व्यावहारिक समाधानों तथा सर्वोत्तम व्यवहारों पर परस्पर कियात्मक कार्यशालाओं का आयोजन करके किसान दिवस का आयोजन।
- हिटत क्षेत्र बनाने के लिए पिटसर के भीतर वृक्षारोपण अभियान और एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को हतोत्साहित करने वाले अभियान।
- स्वच्छता विषयों पर सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण सत्रों, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों सिंहत जन जागरुकता गतिविधियां।







Swachh Bharat Mission Grameen Volume 1 | Issue 25









रक्षा मंत्रालय

- एसक्यूएई (एल), मुंबई में स्वच्छता पखवाड़ा समारोह, पोस्टर और स्लोगन अभियान जैसी गतिविधियां।

आयुध निदेशालय (C&s):

- समापन समारोह और पुरस्कारों का वितरण।
- संवाददाता सम्मेलन का आयोजन।
- पीआईबी विज्ञप्ति जारी करना।















DDWS द्वारा आयोजित कलेक्टर संवाद.

DDWS ने कलेक्टरों, डिप्टी कमिश्नरों और जिला पंचायतों के सीईओ द्वारा SBMG के तहत कार्यान्वित किए गए अभिनवयुक्त सर्वोत्तम परिपाटियों को उजागर करने के लिए इस महीने अपनी मासिक कलेक्टर संवाद पहल को फिर से शुरू किया। संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, एसबीएम-जी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर को एक कलेक्टर संवाद आयोजित की गई, जिसमें पांच राज्यों के जिला अधिकारियों ने अपने अनुकरणीय कार्यों को प्रस्तुत किया:

- श्री शीलेंद्र सिंह, DC, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
- श्री विशाख, DM, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
- श्री एनएसके उमेश, DC, एनिकुलम, केरल
- सुश्री मेघा भारद्वाज, DC, कोडरमा, झारखंड
- डॉ. आनंद के, CEO, जेडपी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक





छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश: श्री शीलेंद्र सिंह, DC



अलीगढ़, उत्तर प्रदेश: श्री विशाख, DM



एनक्लिम, केरल: श्री. एनएसके उमेश, DC



कोडरमा, झारखंड: सुश्री मेघा भारद्वाज, DC



दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक: डॉ. आनंद के, CEO- जेडपी







SPM NIWAS-कोलकाता

दिसंबर २०२४ में, SPM NIWAS ने सात प्रशिक्षण आयोजित किए जिसमें कुल ४०२ प्रतिभागियों ने भाग लिया।

निम्न विषयों पर पांच भौतिक प्रशिक्षण:

- 1. ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन
- 2. जल और स्वच्छता में पीआरए में महारत हासिल करना
- 3. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- 4. शहरी सीवेज शोधन संयंत्रों के साथ सामंजस्य में मलीय कचरा प्रबंधन को बढावा देना
- 5. लाइट हाउस पहल के तहत ब्लॉक स्तरीय समन्वयकों के लिए एसबीएम (जी) पर प्रशिक्षण

निम्न विषय पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण:

ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी-कम्पोस्टिंग और खतरनाक घरेलू कचरे का प्रबंधन

जनवरी २०२४ में, SPM-NIWAS ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रारूप के माध्यम से निम्नलिखित प्रशिक्षण आयोजित करने की योजना बना रहा है।

- तरल अपशिष्ट और मलीय गाद प्रबंधन
- SIRD और राज्य मान्यता प्राप्त संस्थानों (वॉश सेल) के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (ToT)
- ग्रीन हाईवे (सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग)
- FSSM सह-शोधन दृष्टिकोण
- एसबीएम-जी २.० पर मास्टर प्रशिक्षकों का पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- जल और स्वच्छता में पीआरए
- वर्मी-कम्पोस्टिंग और सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग
- PWMU का प्रबंधन

प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण करने हेतु- यहाँ क्लिक करें



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:-

मोहम्मद इश्फाक mohd.ishfaq@ias.gov.in पर चैताली मोडल chaitalimondal@kpmg.com पर







केंद्रीय मंत्री ने एसबीएम-जी की प्रगति की समीक्षा की: दिनांक 3 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान



केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने दिनांक ३ दिसंबर २०२४ को हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण स्वच् छता से संबंधित प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में उपलब्धियों और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले क्षेत्रों को उजागर किया गया, जिसमें एसबीएम-जी की स्थिरता और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।

हिमाचल प्रदेश: स्वच्छता लक्ष्यों को हासिल करने में विशिष्ट उपलब्धि

हिमाचल प्रदेश ने सराहनीय प्रगति की है, इसके 17,596 गांवों में से 90% को खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस घोषित किया गया है, और 63% ODF प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। तथापि, यह राज्य 34 राज्यों में 21वें स्थान पर है, जो मार्च 2025 तक अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अंतिम प्रयास की आवश्यकता का संकेत देता है। जबिक राज्य के अधिकांश गांवों में ठोस और ग्रेवाटर प्रबंधन संबंधी प्रणालियाँ मौजूद हैं (क्रमशः 78% और 86%), जल निकासी के अंतिम बिंदुओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करने और अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों की संचालन संबंधी कार्यशीलता सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता है।

राजस्थान: स्थिरता के लिए प्रयास के साथ प्रगति

स्वच्छता के संबंध में राजस्थान के प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं, इसके 43,447 गांवों में से 98% ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है और 85% ओडीएफ प्लस मॉडल बेंचमार्क को पूरा कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर 10वें स्थान पर राज्य की स्थिति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, लेकिन मंत्री ने शेष समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अधिक पढ़ने के लिए, <mark>यहां क्लिक करें</mark>











स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM-G) का एक महत्वपूर्ण घटक गोबरधन (गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) पहल जैविक कचरे को संपीड़ित बायोगैस (CBG) और जैविक खाद जैसे मूल्यवान संसाधनों में बदलने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटिल ने दिनांक 3 दिसंबर, 2024 को इस पहल की प्रगति का मूल यांकन करने और इसके भावी कार्यनीतियाँ बनाने के लिए नौ प्रमुख हितधारक मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की।

केंद्रीय बजट 2023-24 ने गोबरधन योजना के तहत 200 नए CBG संयंत्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। अब तक, 37 CBG संयंत्र कार्यशील हैं, और 133 विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जो 2020 में 19 कार्यशील संयंत्रों से 2024 में 125 कार्यशील संयंत्रों तक की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है।











माननीय जल शक्ति मंत्री ने 10 दिसंबर को पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में SBM-G की प्रगति की समीक्षा की



Hon'ble Union Minister, C R Patil with Smt Padha Ravindra Singh, Hon'ble Minister of State for Panchayat and Rural Development of Machya Pradesh



Hon'ble Union Minister, C R Patil reviewing UP Progress with State Officials



Hon'ble Minister CR Patil with Shri Shrawon Kumar, Hon'ble Minister of Bihar Rura Development



Hon'ble Union Minister, C R Patil with Sh. Hardeep Singh Mundian, Hon'ble Minister for Revenue, Rehabilitation and Disaster

SBM-G पूरे भारत में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दिनांक 10 दिसंबर, 2024 को माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल ने पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) के अधिकारियों के साथ पंजाब, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य प्रगति का मूल्यांकन करना, चुनौतियों का समाधान करना और आगे बढ़ते हुए स्थायी परिणामों के लिए रणनीति बनाना था। केंद्रीय मंत्री ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामुदायिक गरिमा में सुधार लाने में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए रेखांकित किया कि स्वच्छता बुनियादी ढांचे से परे फैली हुई है। जैसा कि उन्होंने कहा, "स्वच्छता केवल एक बुनियादी ढांचागत लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक मिशन है जो ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य और गरिमा को आकार देता है।

राज्य द्वारा प्रमुख उपलब्धियां

पंजाब

• 98% गांव ODF प्लस हैं, जिनमें 87% पूर्ण ग्रे वाटर प्रबंधन प्राप्त कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश

• ९९% गांव ODF प्लस हैं, जिनमें से ९५% ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा प्राप्त कर रहे हैं।

उत्तर परेश

• 98% गांव ODF प्लस हैं, जिनमें एसबीएम-जी कार्यान्वयन के लिए 1 लाख से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है।

बिहार

• 92% गाँव ODF प्लस हैं, जिनमें ग्रे वाटर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कवरेज क्रमशः ९१% और ८०% है।



स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वॉल्यूम १ | इश्यू २५





हमारा शौचालय: हमारा सम्मान स्वच्छता और गरिमा की यात्रा



विश्व शौचालय दिवस (१९ नवंबर) पर शुरू किया गया "हमारा शौचालय: हमारा सम्मान" (HSHS) अभियान, १० दिसंबर को समाप्त हुआ, जो स्वच्छता, गरिमा और मानवाधिकारों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देने के लिए मानवाधिकार दिवस के साथ संरेखित है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) द्वारा आयोजित, इस तीन सप्ताह के अभियान ने पूरे भारत में समुदायों को एकत्रित किया, स्वच्छता को एक साझा जिम्मेदारी और गर्व के स्रोत के रूप में उजागर किया।

HSHS अभियान की उपलब्धियां

- •सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) में सुधार: 1.54 लाख से अधिक CSC का मूल्यांकन किया गया और उनकी कार्यशीलता में सुधार किया गया, जिसमें 70% से अधिक मौजूदा परिसर शामिल हैं।
- •नए शौचालयों को मंज़ूरी: 3.35 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) को मंज़ूरी दी गई, जिससे स्वच्छता संबंधी महत्त्वपूर्ण अंतराल को दूर किया गया।
- •सामुदायिक भागीदारी: 50,500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 38 लाख से अधिक लोगों ने स्वच्छता अभियान और रात्रि चौपालों जैसी जमीनी स्तर की गतिविधियों में भाग लिया।
- •स्थानीय अभिशासन को सुदृढ़ बनाना: 600 से अधिक ज़िला जल और स्वच्छता मिशन (DWSM) की बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें हर स्तर पर हितधारकों को शामिल किया गया।







बस्तर, छत्तीसगढ़ में अपशिष्ट प्रबंधन को सामग्री पुनर्चक्रण केंद्र (MRC) के माध्यम से अपशिष्ट से धन में बदलना



Swachh Centre-MRC shed at Bastar, Chhattisgarh

Effluent Treatment Plant (ETP)



स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) के तहत, छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक अग्रणी सामग्री पुनर्चक्रण केंद्र (MRC) की स्थापना की गई है। यह भारत में अपनी तरह की पहली सुविधा है और HDFC बैंक- CEE समर्थित परियोजना "ग्रामीण और शहरी परिदृश्य सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त" का हिस्सा है।

बस्तर परियोजना अद्वितीय है क्योंकि इसने स्वच्छ केंद्र नामक एकल, एकीकृत पहल में एक सामग्री वसूली और पुनर्चक्रण की स्थापना की है। जिला पंचायत बस्तर और स्थानीय निकायों द्वारा समर्थित, MRC 71 ग्राम पंचायतों के 114 गांवों को पूरा करता है, जो एक सर्कुलर इकोनोमी दृष्टिकोण के माध्यम से अभिनव अपशिष्ट प्रबंधन और स्थिरता के लिए एसबीएमजी की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। दिनांक 13 जून 2024 को श्री महेश कश्यप, सांसद बस्तर और श्री किरण देव, विधायक जगदलपुर ने एमआरसी का उद्घाटन किया। एमआरसी ने पहले ही पर्यावरणीय स्थिरता और संसाधन दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

एसबीएमजी लक्ष्यों का समर्थन करने वाली स्वच्छ केंद्र-अत्याधुनिक सुविधा

ये स्वच्छ केंद्र (जो MRF और MRC की इकाइयां हैं) विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कचरे को कुशलतापूर्वक संसाधित करने के लिए उन्नत मशीनरी का उपयोग करते हैं। जुलाई 2024 से कार्यशील, इन स्वच्छ केंद्रों ने मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक (MLP), लो-डेंसिटी पॉलीथीन (LDPE), और हाई-डेंसिटी पॉलीथीन (HDPE) सहित 59.13 मीट्रिक टन (MT) प्लास्टिक कचरे को संसाधित किया है। आज की स्थिति के अनुसार, 40.24 मीट्रिक टन पुनर्चीक्रेत MLP को आगे की प्रक्रिया के लिए निर्माताओं को भेजा गया है।

अधिक पढ़ने के लिए, <mark>यहां क्लिक करें</mark>



वॉल्यूम १ | इश्यू २५





गंजम, ओडिशा में एक क्षेत्रीय कार्यशाला: स्थिरता अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना



'सूखा एंड प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: स्थिरता' नामक दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला। समावेशिता। भागीदारी (अपशिष्ट शोधन) २०-२१ दिसंबर, २०२४ को ओडिशा के गंजम में आयोजित की गई थी। डीडीडब्ल्यूएस, ओडिशा सरकार, जिला परिषद गंजम, CEE और CORE द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस पहल ने नवीन अपशिष्ट प्रबंधन कार्यनीतियों का पता लगाने के लिए प्रमुख अधिकारियों और विशेषज्ञों को एकत्रित किया।

कार्यशाला की शुरुआत हिंजलीकट, गंजम में सामग्री रिकवरी सुविधा (MRF) के कार्यप्रदर्शन के साथ हुई। इस कार्यप्रदर्शन का नेतृत्व श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (SBM) ने किया था और इसमें विरेष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यप्रदर्शन को CEE द्वारा सुगम बनाया गया था और ओडिशा, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और इसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 60 से अधिक विरष्ठ अधिकारियों की सिक्रय भागीदारी देखी गई थी। चर्चा MRF की कार्यशीलता और प्रभाव पर केंद्रित थी, जिसमें पिरपत्र अर्थव्यवस्था प्रथाओं को आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया था।



अधिक पढ़ने के लिए, **यहां क्लिक करें** 🚫







मुजफ्फरपुर, बिहार में स्वच्छता प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन



Children and SHG members inaugurating the Sanitation Technology Park at Sakra, Muzaffarpur, Bihar.





SHG Members displaying the low-cost sanitation products, gaining attention from the District Administration, Muzaffarpur, Bihar.



Children explaining the functionality and benefits of each technology displayed at the technology park.

वर्ष 2014 के बाद से, बिहार ने स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के तहत किए गए प्रयासों के माध्यम से स्वच्छता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। शौचालय कवरेज में वृद्धि, समुदाय के नेतृत्व वाले अभियान और स्वच्छता जागरूकता में वृद्धि महत्वपूर्ण मील के पत्थर को चिह्नित करती है, मुजफ्फरपुर एक मॉडल जिले के रूप में उभर रहा है। हालांकि, चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वभौमिक रूप से सुरक्षित, स्थायी स्वच्छता प्राप्त करने में। सभी के लिए बुनियादी सुविधाओं से धारणीय प्रणालियों तक प्रगति हेतु निरंतर निवेश और नवाचार आवश्यक हैं।

स्वच्छता प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन यूनिसेफ ने आजीविका अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (ILRT) की तकनीकी सहायता से जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के सहयोग से बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के सकरा ब्लॉक में स्वच्छता प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया। यह जिले की स्वच्छता यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस पार्क में जलवायु अनुकूल स्थायी स्वच्छता प्रौद्योगिकियां हैं जैसे जैव डाइजेस्टर के साथ उठाया शौचालय, इको-सैन शौचालय, निर्मित आईभूमि, मैजिक पिट, जंक्शन चैंबर, वर्षा जल संचयन संरचना, एनएडीईपी खाद, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब (WSP), और निर्मित आईभूमि। पार्क स्थानीय अधिकारियों, PRI सदस्यों और सामुदायिक हितधारकों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करेगा।



अधिक पढ़ने के लिए, <mark>यहां क्लिक करें</mark>





स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वॉल्युम १ | इश्यू २५



स्वच्छ खोज

नीचे क्रॉसवर्ड पहेली को पूरा करें



Hintis: Gobardhan, Dignity, Compost ODF, Plastic Biogas, Segregation Waste, Cleanliness, Sanitation











विशेष सचिव का कार्यालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार।